



---

## **Prabhat Khabar's Senior Journalist Rajeev Pandey Received 'Laadli Media Award' | Jharkhand | 25 Oct 2023**

### **Why In News?**

Recently, Rajiv Pandey, a senior journalist of Prabhat Khabar's Ranchi unit, has been awarded the 'Laadli Media Awards 2023' by 'Population First', a prestigious organization working in the field of gender equality.

### **Key Points:**

- The Laadli Media Award is given by the 'Population First' organization for promoting gender sensitivity. The Laadli media award was announced by the organization on October 21 this year.
- More than 850 journalists from across the country in 13 languages had submitted entries for the award, out of which 87 were selected and felicitated by the jury members. Apart from these, 31 journalists were given jury commendation letters.
- Prabhat Khabar has received the award at the 13th Laadli Media and Advertising Award for Gender Sensitivity (Regional) 2023 organized by Population First Organization. Last year, another journalist of Prabhat Khabar, Guruswaroop Mishra, was also honoured with the award.
- He received the award for a story on domestic workers titled 'Poor condition of domestic workers, no leave and no proper wages' published by Rajiv Pandey, chief correspondent of Prabhat Khabar Ranchi unit.
- The vice-chancellor of Baba Amte Divyang University, Jaipur, Prof. S.K. Singh was also present on the occasion. Dr Dev Swarup, Head of Policy and Partnerships, United Nations Population Fund, Jaideep Biswas, Programme Management Specialist, UNFPA, Anuja Gulati, Programme Management Specialist and Kalyan Singh Kothari, Secretary, Lok Samvad Sansthan felicitated Pandey.
- It is worth mentioning that Rajiv Pandey has already been given three fellowship awards by Chennai-based institute REACH. In the year 2014, Jharkhand has received fellowships on the status of TB disease, non-communicable diseases in the year 2019 and diabetes in the year 2023.

//



# घरेलू कामगारों की स्थिति खराब, न छुट्टी और न उचित मेहनताना

**राजेश पांडेय**, रांची

झारखंड में घरेलू कामगारों में 70% को मासिक मजदूरी मात्र 3,000 रुपये और 10% को अधिकतम 4,000 रुपये का वेतनमान मिलता है, जबकि 20% कामगार 2000 रुपये में भी काम करने को विवश हैं। घरेलू कामगारों में 40.9% शिक्षित हैं, जबकि झारखंड एंटी ट्रेडिंग नेटवर्क और स्पार्क संघों द्वारा 'झारखंड के घरेलू काम करनेवालों की स्थिति' पर रिपोर्ट गैर सही में मिली है।

**68.6% को राह में घर दिन खी मिलती है छुट्टी** : रिपोर्ट में बताया गया है कि 40.9% में 13.1 को निराश्रित और पढ़ना आता है, जबकि 22.6% ने पंचवर्षी तक, 3.6% ने मीट्रिक और 1.5% ने इंटरमीडिएट को पढ़ाई पूरी की है, कम वेतन और शिक्षित होने के

बाद भी 68.6% को मासिक मजदूरी मात्र चार दिन की छुट्टी मिलती है, अन्य सामाजिक अवसर और एंटीट्रेड के अनुसार छुट्टी लेते हैं, 50%से अधिक घरेलू कामगार दोबारा या मोजन ( उनके ड्रग से जगन ) अपने निवेश के घरो में रहते हैं, लेकिन वहां के किसी भी व्यंजन का उपभोग नहीं करते हैं, घरों पर फेडरल उनको खाना भी खाना पढ़ते हैं, वहां कुछ तो आर्टिफिशियल कैंडी के बने खा लेते हैं, अगर इनके आर्थिक हालात को ध्यान में रखें, तो लगभग 85% घरों में काम करनेवालों का कच्चा घर है और अलग किराने नहीं है, इनके अलावा उनको घरेलू काम करने के पाने पर आंशिक रजाना पढ़ना है, उनके कच्चे करने के समय बा भी आकलन किया गया है, जिसमें 47.6% आंगन नहीं कर पाते हैं,

## झारखंड एंटी ट्रेडिंग नेटवर्क और स्पार्क की सर्वे रिपोर्ट



**40.9%** घरेलू कामगार शिक्षित

**59.1%** घरेलू कामगार अशिक्षित पाये गये

**67% के पास राइडकिल और 10% के पास टेलीविजन**

रिपोर्ट की मने तो घरेलू कामगारों की संख्या भी संतोषदायक नहीं है, 67 फीसदी के पास राइडकिल, 8 फीसदी के पास प्रेसर कुकर, 34 फीसदी के पास रेडियो, 10 फीसदी के पास टेलीविजन और लगभग 6 फीसदी के पास मिजती के पड़े हैं, इन्हीं समझौते स्थिति भी बेहतर नहीं है, डेन, बिजली और शौचालय की सुविधा भी ठीक से नहीं मिलती है, इन्हीं आठ 81.8 फीसदी कम करने और 10.2 फीसदी कृषि से होती है, वहीं 1.5 फीसदी के पास व्यवसाय और 6.6 फीसदी के पास आय के अन्य स्रोत हैं,

**झारखंड के घरेलू काम करने वालों की स्थिति पर हुई चर्चा**

झारखंड एंटी ट्रेडिंग नेटवर्क और स्पार्क संघों द्वारा 'झारखंड के घरेलू काम करने वालों की स्थिति' पर चर्चा की गयी, कटौतवादी स्थिति टाल करत इस में अवैधानिक इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता तारामणि राहु ने कहा कि अनुसूचित जातिये व जनजातिये के उद्धार के लिए सरकार और वीर सरकारों सरकारों को मिलकर काम करना होगा, अंतरिम इंडिया की सभना सुनिने में कहा कि डोमरेटवर्क केसों जब अपने समस्या लेबर पुलिस अथवा सरकारों सरकारों के पास जाते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, कई बार उनके ही वरिष्ठ पर सवाल उठाया जाता है, और फरार मुकाम में कहा कि इन्हीं मध्य की जरूरत है,